साप्ताहिक

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 25 नवंबर-01 दिसंबर, 2024 वर्ष-10, अंक-32

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

भोपाल में होगी प्रदेश की पहली हाईटेक गौशाला: पांच साल में 20 फीसदी दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य

मध्यप्रदेश में गौ-माता से संबंधित डिग्री-डिप्लोमा कराएगी सरकार

-सीएम डॉ. मोहन यादव बोले-जिसके घर में गाय का कुल, वह घर गोकुल

25 एकड़ क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी गौ-शाला

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गौ-माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। जो भी गौवंश का पालन करे वही गोपाल है, जिसके घर में गाय का कुल वह घर गोकुल है। अतः प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को घर में गौपालन के लिए पहल करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के भेदभाव के हमें गौ-पालन को प्रोत्साहित करना है। परंपरागत रूप से भी भारत में सभी धर्म और जाति के लोग गौ-पालन करते हैं और यही हमारी सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भोपाल के ग्राम बरखेड़ी डोब में 10 हजार गायों की क्षमता वाली हाईटेक गौ-शाला के भूमि-पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि भोपाल जिले के बरखेड़ी डोब ग्राम में 25 एकड़ क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए की लागत से गौ-शाला का निर्माण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाईटेक गौ-शाला भूमि-पूजन स्थल पहुंचने पर सर्वप्रथम गौ-माता को दुलार कर नमन किया तथा उन्हें आहार सामग्री अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश में गौवंश संरक्षण और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए संचालित गतिविधियों पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेल मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय, जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर नौरंग सिंह गुर्जर सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

» मध्यप्रदेश में घर-घर बछिया उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाएगा

» गौ-शाला के लिए सक्रियता से कार्य जारी, 300 गौ-शालाओं का पंजीयन

» राजधानी में 10 हजार गायों की क्षमता वाली हाईटेक गौशाला का भूमिपूजन

» भोपाल का सूखी सेवनिया गांव में बनेगा सीएम राइज स्कूल

बढ़ रहा है गौ-शालाओं का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के अधिकांश देशों में दुग्ध की आपूर्ति गौ-माता ही करती हैं। सनातन संस्कृति में गौ-माता का महत्व इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिये गौ-दान आवश्यक बताया गया है। बदलती जीवनशैली में गौ-शालाओं का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य शासन द्वारा विशाला गौ-शाला स्थापित करने की दिशा में सक्रियता से कार्य किया जा रहा है, वर्तमान वर्ष में अब तक 300 गौ-शालाओं का पंजीयन हुआ है। विभिन्न सामाजिक संगठन भी गौ-शाला संचालन में पहल कर रहे हैं। गौ-पालन परिवारों के आर्थिक सशक्ति करण के साथ परिवार को पोषक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में भी सहायक है। अतः घर-घर बछिया उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकार शीघ्र ही दुग्ध उत्पादन पर बोनस देने की व्यवस्था कर रही है। वर्तमान में मध्यप्रदेश, देश के कुल दुग्ध उत्पादन में 9 प्रतिशत का योगदान देता है। इसे अगले पांच वर्ष में 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।

सूखी सेवनिया रोड को होगी फोरलेन

मुख्यमंत्री ने शासकीय विद्यालय सूखी सेवनिया को सीएम राइज विद्यालय बनाने और सूखी सेवनिया रोड को विभागीय मद अनुसार फोरलेन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बरखेड़ी डोब क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से गौ-माता से संबंधित डिग्री-डिप्लोमा कोर्स आरंभ किया जाएगा।

लाखों गायों की देखभाल का संकल्प

स्वामी अच्युतानंद ने गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सरकार गठन के बाद अभी तक के अल्प समय में प्रदेश में लगभग 50 हजार गायों के पालन-पोषण की व्यवस्था की है। प्रदेश की लाखों गायों की देखभाल का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश सरकार इस वर्ष को गौ-संवर्धन वर्ष के रूप में मना रही है। आज यहां गौलोक धाम की स्थापना इसी कड़ी में एक सार्थक प्रयास है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास के लिए सभी महात्मा, सभी ऋषिगण उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं। गौ-माता का पालन-पोषण हम सभी सनातनियों का दायित्व है। हमें इस प्रकार के प्रयास करने चाहिएं कि हर घर में एक गाय रहे। गौ-माता के बिना घर सूना होता है।

एक नजर में...कुछ खास

» गायों को कन्वेयर बेल्ट से मिलेगा आहार और सीसीटीवी से होगी मॉनीटरिंग

» गायों के उपचार के लिए संसाधनों से युक्त चिकित्सा वार्ड का निर्माण कराएंगे

» गौ-शाला का निर्माण 3 चरणों में, प्रथम चरण में 2000 पशु क्षमता का होगा

» भूसा, हरा घास, पशु आहार कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा

» गौ-शाला में गायों के गोबर एवं मूत्र आदि से विभिन्न सामग्री तैयार की जाएगी

किसानों के लिए चिंताजनक-यूक्रेन रूस युद्ध

प्रदेश में खाद की सप्लाई में 25 फीसदी गिरावट

प्रदेश में पिछले रबी के सीजन में 4.41 लाख मीट्रिक टन डीएपी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में इस बार बोवनी के समय डीएपी खाद कम मिल रही है। इसकी वजह है दुनिया में चल रहे युद्ध और संकट। इनकी वजह से खाद की कीमतें बढ़ गई हैं और सप्लाई में 25 फीसदी तक की कमी आई है। हालांकि कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके वैकल्पिक खाद एनपीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसानों को पिछले साल की तरह डीएपी नहीं मिल पा रही है। इससे खाद की कमी का अहसास हो रहा है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि डीएपी की कमी है, लेकिन खाद की कमी नहीं है क्योंकि एनपीके उपलब्ध है। खत्म हुए हफ्ते में कुछ दिनों के लिए आपूर्ति में दिक्कत आई थी, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। लेकिन इसी वजह से कमी की आशंका और बढ़ गई। अधिकारियों ने बताया कि इस समय 28 रैक में खाद आ रहा है, जिसमें 24 रैक डीएपी और चार रैक एनपीके है। यह खाद जल्द ही राज्य में पहुंच जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन-रूस युद्ध, गाजा संकट और दुनिया के अन्य मुद्दों ने स्वेज नहर के रास्ते परिवहन को प्रभावित किया है, इस प्रकार इस वर्ष डीएपी आपूर्ति में गिरावट आई है।

2.4 लाख मीट्रिक टन मिली खाद

अब तक 2.4 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं और वितरित किया जा रहा है। 75,000 मीट्रिक टन और आ रहा है, और उसके बाद हमें 1 लाख मीट्रिक टन और मिलेगा। पिछले साल रबी के सीजन में राज्य में लगभग 4.41 लाख मीट्रिक टन डीएपी का उपयोग हुआ था।

हो रही कालाबाजारी

राज्य में डीएपी के कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं। किसान संगठनों ने इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने की धमकी भी दी है।

शिवराज का एलान-किसान को नहीं होगा नुकसान

प्याज-टमाटर-आलू के 'मॉडल रेट'

भोपाल। जागत गांव हमर

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम गिरते हैं तो किसान को नुकसान होता है, इसलिए आईसीएआर लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर मॉडल रेट तय करेगा। बाजार रेट से अंतर पर नुकसान केन्द्र और राज्य सरकार 50-50 फीसदी वहन करेंगे। शिवराज महाराष्ट्र में मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही। शिवराज ने कहा कि प्याज के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया गया है, एक्सपोर्ट शुल्क 40 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी किया गया है। जिससे प्याज के दामों में वृद्धि हुई है। पाम ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया से जीरो पर्सेंट ड्यूटी पर आयात किए जाते थे, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 27.5 फीसदी की गई है। ताकि किसान को सोयाबीन के ठीक दाम मिल सके। सोयाबीन की एमएसपी है 4892 रुपए, केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को अनुमति दी है कि, वह एमएसपी पर सोयाबीन खरीदें। सोयाबीन में नमी की सीमा को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान के बाद मप्र के किसानों को भी राहत मिल गई है।

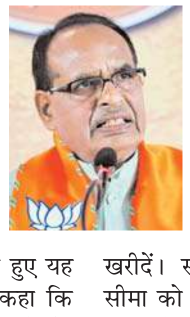

नर्मदा किनारे किया जाए पौधरोपण, प्रदेश की हर पंचायत में कार्य समय पर पूरा कराया जाए

पंचायतों में रिजल्ट ओरिएंटेड काम कराओ सभी तालाबों-बावड़ियों को भी संवारा जाए

पंचायत मंत्री ने कहा

पौधरोपण के बाद उनका सर्वाइवल रेट अधिक रहे इस पर भी काम किया जाए

भोपाल। जागत गांव हमार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायतों में रिजल्ट ओरिएंटेड काम किए जाएं। सभी तालाबों एवं बावडियों का जीर्णोद्वार करें। इसके लिए पंचायत बार कार्य-योजना बनाए चरणबद्ध तरीके से काम करें। पौधरोपण के बाद उनका सर्वाइवल रेट अधिक रहे, इस पर भी कार्य किया जाए।

मंत्री पटेल ने मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा में गत 15 नवंबर की स्थिति में जिन जनपद पंचायतों में श्रम सामग्री का अनुपात सही होगा, उनमें ग्रेवल रोड, खेत तालाब और अन्य नए कार्य शुरू करने की मंजूरी जारी की जा रही है। यह राशि एक से तीन करोड़ रुपए तक स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैन मुनियों के प्रवास मार्ग चिन्हित कर प्रमुख मार्गों पर उनके रुकने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। शासकीय भूमि पर समुचित पौधरोपण किए जाएं।

सघन पौधरोपण के निर्देश

मंत्री पटेल ने कहा कि ग्राम पंचायतों में खेत सड़क एवं सुदूर सड़क योजना में सड़कों की मांग एक बार में ही चिन्हित कर ली जाए, जिससे स्वीकृति के लिए निर्णय लिया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि स्कूल शिक्षा विभाग के तहत स्कूलों की बाउंड्रीवॉल निर्माण में मनरेगा कन्वर्जेंस रेट भी तय किया जाए। मनरेगा में किए जा रहे पौधरोपण को बाउंड्रीवॉल से सुरक्षित किया जाए। पौधे जल-स्त्रोतों के निकट ही लगाए जाएं कि ये पौधे सुरक्षित भी रहें। उन्होंने नर्मदा नदी के किनारों पर सघन पौधरोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की जनपद स्तर पर क्लस्टर बैठक नियमित रूप से होना चाहिए।

मेंटेनेंस पर भी विशेष फोकस

मंत्री पटेल ने निर्देश दिए कि विश्राम घाट शेड के साथ बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जाए एवं परिसर में पौधरोपण भी किया जाए। उन्होंने बाउंड्रीवॉल निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करने का पत्र केन्द्र सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए साइट सिलेक्शन उचित तरीके से किया जाए एवं उनके मेंटेनेंस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। ग्रेवल रोड के निर्माण में यदि जरूरी हो, तो पुलिया के निर्माण के लिए राशि अलग से मंजूर की जाए। उन्होंने बांस के उपयोग को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि बांस से बनी बाउंड्रीवॉल प्राकृतिक रूप से मजबूत और सुंदर होती है।

बांस रोपण करने पर जोर

पंचायत मंत्री ने पौधरोपण क्षेत्र की बाउंड्रीवॉल पर बांस रोपण करने पर जोर दिया। उन्होंने पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत एवं सामुदायिक भवन बनाने के कार्य की भी समीक्षा की। विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में प्रावधानों पर स्पष्ट रूप से विचार करने के लिए निर्देश दिए। पंचायतों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से मिलकर स्पष्ट कार्य योजना भी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने का कि विधानसभा के लंबित मामलों का निराकरण समय-सीमा में किये जाए।

अनूपपुर की ग्राम पंचायत में एक अनोखा कारनामा

कमीशन के लिए पंचायत ने पारित किया प्रस्ताव जिला पंचायत ने सरपंच-पंचों को थमाया नोटिस

अनूपपुर। जागत गांव हमार

अनूपपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। जहां ग्राम पंचायत ने विभिन्न निर्माण कार्यों में पंच एवं सरपंच को कमीशन देने का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही इस प्रस्ताव के साथ कमीशन ना देने वाले सचिव का अन्यत्र स्थानांतरण किए जाने का प्रस्ताव भी किया गया। जब सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी सामने आई तो प्रशासन ने आनन-फानन में इस पर ग्राम पंचायत सरपंच एवं पंचों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। पुष्पराजगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सालार गोंदी में पंच एवं सरपंचों ने पहले तो विभिन्न कार्यों में ग्राम पंचायत सचिव से कमीशन की मांग की, जिसे न देने पर विधिवत ग्राम पंचायत की ग्राम सभा आयोजित की गई। जहां 11 सितंबर को ग्राम सभा की बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया कि पंचों को 5 प्रतिशत सरपंच को 10 प्रतिशत एवं उपसरपंच को 7 प्रतिशत कमीशन सचिव प्रदान करें। प्रस्ताव में यह भी लिखा हुआ है कि सचिन जयंती पनारिया ने आज तक 1 रुपए भी कमीशन राशि पंचायत पदाधिकारी को प्रदान नहीं की है, जिसको देखते हुए सचिव का स्थानांतरण अन्यत्र किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

16 को जारी किया नोटिस

इस मामले के सामने आने के बाद न्यायालय या पर कलेक्टर विकास मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर ने ग्राम पंचायत सागर गोंदी के सरपंच विक्रम प्रसाद, पांच सोनिया बाई, तुलसी बाई, नरबदिया बाई, मीराबाई, ओम प्रकाश, सुनी बाई, सरिता बाई, हेमलता बाई, दुर्गा सिंह, राजेश कुमार, बृजलाल, ज्ञानवती, पतिलाल, बैसाखू माझी ,ओम प्रकाश सिंह को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही संतोष जनक जवाब न होने पर मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 हानी दुरुपयोग के लिए पंचों का दायित्व के तहत शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के मामले में धारा 40 के तहत पद से हटाने की चेतावनी दी गई है।

जल संसाधन मंत्री सिलावट ने राजस्थान के मंत्री से की चर्चा

अब चंबल नहर प्रणाली से मिलेगा मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी

- » राजस्थान ने दिलाया भरोसा कि जल्द ही पूरा पानी छोड़ा जाएगा
- » चंबल नहर प्रणाली से श्योपुर, मुरैना-भिंड जिले में होती सिंचाई

भोपाल। जागत गांव हमार

चंबल नहर प्रणाली से मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करने के लिए प्रदेश के जल संसाधन एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट लगातार प्रयासरत हैं। इस सिलसिले में उन्होंने राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत से टेलीफोन पर चर्चा की। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री ने मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराने के लिए सिलावट को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि चंबल नहर प्रणाली से पार्वती एक्वाडक्ट पर जल्द ही मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि चंबल नहर प्रणाली से चंबल संभाग के श्योपुर, मुरैना व भिंड जिले की सिंचाई के लिए पानी मिलता है। ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री सिलावट ने बताया कि चंबल नहर प्रणाली से श्योपुर, मुरैना व भिंड जिले के अंतर्गत 3 लाख 62 हजार 100 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। उन्होंने बताया बीते दिनों मध्यप्रदेश-राजस्थान अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल कोटा की 29वी तकनीकी समिति की बैठक में चंबल मुख्य नहर से मध्यप्रदेश की मांग के अनुसार पार्वती एक्वाडक्ट पर 3900 क्यूसेक पानी निरंतर उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ था, लेकिन मात्र 1800 से लेकर 2100 क्यूसेक पानी ही मप्र को दिया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री से चर्चा की है। जल संसाधन मंत्री सिलावट ने बताया कि राजस्थान के जल संसाधन मंत्री ने जल्द से जल्द मध्यप्रदेश के हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध कराने का को आश्वास्त किया है। सिलावट ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार अपने हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए लगातार राजस्थान सरकार के संपर्क में है।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मिलिंग नीति की खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने की समीक्षा

मंत्री की दो टूक-प्रमुख सचिव-आयुक्त ऑफिस से निकलें बाहर, उपार्जन केंद्रों का करें औचक निरीक्षण

भोपाल। जागत गांव हमार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के मिलिंग नीति की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को कड़े निर्देश दिए कि उपार्जन के दौरान या उसके बाद होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त उपार्जन केन्द्रों का औचक निरीक्षण करें।

मंत्रालय में प्रस्तावित मिलिंग नीति की समीक्षा करते हुए खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अफसर कड़े निर्णय लेने से गुरेज न करें। व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनिमितता पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। उपार्जन में गड़बड़ी रोकने के लिए उड़न दस्ता गठित करें। उड़नदस्ता औचक रूप से उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। मंत्री राजपूत ने कहा कि मैदानी स्तर पर जिला प्रबंधक नियमानुसार कार्य करने में कोई कोताही न बरतें। अफसरों को निर्देश दिये गये कि उपार्जन कार्य में संलग्न सर्वेयरों पर सतत् निगरानी रखें, जिससे वे उपार्जन के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही न करें।

उन्होंने व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कुछ नई कार्य-योजना बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य रश्मि अरूण शमी, आयुक्त खाद्य सिबि चक्रवर्ती, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम पीएन यादव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मशीनों से होगी अनाज की सफाई, मंडला में पायलेट प्रोजेक्ट

खाद्य मंत्री राजपूत ने निर्देश दिए कि भारतीय खाद्य निगम को उच्च गुणवत्ता का चावल प्रदान करने के लिए अनाज की सफाई मशीनों से कराई जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस कार्य को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में मंडला से शुरुआत की जाएगी। इसे बाद में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे भारतीय खाद्य निगम को गुणवत्ता युक्त चावल दिया जा सके।

20 दिन में मानक स्तर का चावल जमा कराना अनिवार्य

प्रस्तावित नई मिलर्स नीति 2024-25 में पहली बार दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें चावल की सूचना मिलर्स को प्राप्त होने के दिनांक से 20 दिवस में मानक स्तर का चावल जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने की स्थिति में मिलर्स पर 2 रुपए प्रति दिन प्रति क्विंटल का जुर्माना लगाया जाऐगा और एक माह में मानक स्तर का चावल जमा न कराये जाने पर मिलर्स द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मिलर्स द्वारा भारतीय खाद्य निगम को प्रदान किये जाने वाले चावल की मात्रा 60 प्रतिशत से कम प्रदान करने पर मिलर्स को प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी।

कलेक्टर ने कहा-भूसे की हो रही कमी, उद्योग भी हो रहे चौपट

गेहूं की नरवाई और धान के पैरा को जलाने पर उमरिया में लगा प्रतिबंध

उमरिया। जागत गांव हमार

गेहूं और धान की फसल कटाई उपरांत बचे हुए गेहूं के डंठलो यानी नरवाई तथा धान के पैरा को जलाने पर उमरिया कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाया है। उमरिया कलेक्टर धरणेंद्र कुमार जैन ने बताया कि वर्तमान में गेहूं और धान की फसल कटाई अधिकांशतः कंबाइन हार्वेस्टर से की जाती है। कटाई उपरांत बचे हुए गेहूं के डंठलो से भूसा न बनाकर जला देने और धान के पैरा को जला देने से धान का पैरा एवं भूसे की आवश्यकता पशु आहार के साथ ही अन्य वैकल्पिक रूप में एकत्रित भूसा ईंट-भट्टा एवं अन्य उद्योग भी प्रभावित होते हैं। भूसे एवं धान के पैरा की मांग प्रदेश के अन्य जिलों के साथ अनेक प्रदेशों में भी होती है। एकत्रित भूसा 4-5 रुपए प्रति किलो की दर पर विक्रय किया जा सकता है। इसी तरह धान का पैरा भी बहु उपयोगी है। पर्याप्त मात्रा में भूसा/पैरा उपलब्ध न होने के कारण पशु, अन्य हानिकारक पदार्थ जैसे पालिथीन आदि खाते हैं, जिससे वे बीमार होते हैं तथा अनेक बार उनकी मृत्यु हो जाने से पशुधन की हानि होती है। नरवाई का भूसा नवंबर से दो तीन माह बाद दोगनी दर पर विक्रय होता है। कृषकों को यही भूसा बढ़ी हुई दरों पर क्रय करना पड़ता है। इसके साथ ही नरवाई एवं धान के पैरा में आग लगाना कृषि के लिए नुकसानदायक होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। इसके कारण विगत वर्षों में गंभीर अग्नि दुर्घटनाएं घटित होने से व्यापक संपति की हानि हुई है। ग्रीष्म ऋतु में बढ़ते जल संकट में बढ़ोतरी के साथ ही कानून व्यवस्था के विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती है।

हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा

खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जन धन, संपत्ति, प्राकृतिक वनस्पति एव जीव जंतु आदि नष्ट होने से व्यापक नुकसान होने के साथ खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं के नष्ट होने से खेत की उर्वरा शक्ति धीरे-धीरे घट रही है। उत्पादन प्रभावित हो रहा है। खेत में पड़ा कचरा भूसा डंठल सड़ने पर भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते है, जिन्हे जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करना है। आग लगाने से हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गेहूं एवं धान की फसल कटाई उपरांत बचे हुए गेंहू के डंठलो (नरवाई) तथा धान के पैरा को जलाना प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना आवश्यक है। अत्यावश्यक परिस्थितियां निर्मित होने व समयाभाव के कारण सार्वजनिक रूप से जनसामान्य को सूचना देकर आपत्तियों को सुना जाना संभव नहीं है।

धारा-223 के तहत होगी कारवाई

कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सामान्य के हित सार्वजनिक संपति की सुरक्षा पर्यावरण की हानि रोकने एंव लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर के साथ भूसा तैयार करने के लिए स्ट्रा रीपर अनिवार्य करते हुए संपूर्ण उमरिया जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में गेहूं और धान की फसल कटाई उपरांत बचे हुए गेहू के डंठलो व धान के पैरा को जलाने को एकपक्षीय रूप से प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन भा.न्या.सं. की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये किए जा रहे कार्यों का किया अवलोकन

रातापानी वन्य-जीव अभयारण्य के 16 किलोमीटर क्षेत्र का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

भोपाल। जागत गांव हमार

रातापानी वन्य-जीव अभयारण्य में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। भोपाल-इटारसी रेलवे ट्रैक पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये वन विभाग, इको-टूरिज्म और रेलवे के अधिकारी-कर्मचारियों ने संयुक्त भ्रमण किया। भ्रमण में 16 किलोमीटर क्षेत्र के भोपाल-इटारसी ट्रैक पर रेल शमन उपायों, ट्रेन की गति, कचरा निपटान और बाड़ लगाने जैसे अन्य कार्यों का अवलोकन किया।

भ्रमण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश ईको-टूरिज्म डेव्हलपमेंट बोर्ड समीता राजौरा, मुख्य वन संरक्षक भोपाल रवि खरे और रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे।

हाथियों के प्रबंधन का अध्ययन दल पहुंचा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व

भोपाल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिज़र्व के नेतृत्व में अधिकारियों की 18 सदस्यीय टीम तमिलनाडु में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन अध्ययन दौरे पर तीसरे दिन टीम ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया, अन्नामलाई के डीएफओ ने वालपराई क्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन और इसे कम करने के तरीकों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। अन्नामलाई के डीएफओ ने बताया कि पहाड़ी इलाकों और चाय बागानों की बहुलता वाले क्षेत्र में अनूठी चुनौतियां है, जिसमें संघर्ष की प्रकृति अन्य क्षेत्रों से भिन्न है।

ANAMALAI TIGER RESERVE, POLLACHI DIVISION
Mitigation of Human Animal Conflict in Valparai
Anamalai Tiger Reserve

संघर्ष प्रबंधन रणनीतियों को विकसित करने में इलाके की जानकारी और हाथी का व्यवहार महत्वपूर्ण कारक है। वालपराई में इसके लिये जीएसएम-आधारित उन्नत अलर्ट सिस्टम, एनाइडर तकनीक और सौर फेन्स की एक संयोजित तकनीक उपयोग की जाती है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाँका न लगाने की नीति को अपनाया है और इन उपायों के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में हाथियों से संबंधित मृत्यु को शून्य कर दिया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) ने बताया कि अध्ययन दल ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजय राघवन के साथ बातचीत की। राघवन ने बचाव उपकरणों और वाहनों का प्रदर्शन किया। उन्होंने मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली विधियों और हाथी नियंत्रण कक्ष के संचालन के बारे में जानकारी साझा की।

विश्व मत्स्य पालन दिवसः स्वास्थ्य की दृष्टि से मछली का महत्व

» डॉ. माधुरी शर्मा
» सुजीत कुमार राय
- सह-प्राध्यापक, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर, मप्र
- मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर, मप्र

विश्व मत्स्य पालन दिवस, जो हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है । इस दिन की शुरुआत 1997 में हुई थी। 18 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर विश्व मत्स्यपालन मंच की स्थापना की थी। यह दिवस टिकाऊ मत्स्य पालन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और मछली पकड़ने वाले समुदायों की भलाई के महत्व को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य अति.मछली पकड़ने, आवास विनाश और अवैध मछली पकड़ने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही छोटे पैमाने के मछुआरों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर देना है।

इस वर्ष का विषय, भारत का नीला परिवर्तन लघु स्तरीय और संधारणीय मत्स्य पालन को सुदृढ़ बनाना, मत्स्य पालन क्षेत्र में समावेशी विकास और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पर्यावरणीय स्थिरता और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए छोटे पैमाने के मछुआरों को सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित करता है।

मछली में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ की दृष्टि ये बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे कि अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, विटामिन ए, डी, ई, के तथा कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, मिनरल्स, तथा वसा, ओमेगा-3 फैटी एसिड, डीएच और ईपी आदि उपस्थित होते हैं।

मछली को भोजन के रूप में लेने से निम्नानुसार लाभ होते हैं।

हड्डियों को मजबूत करने में: मछली के तेल का सेवन हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। यह हड्डी संबंधी रोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कमजोर हड्डियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। मछली के तेल के सेवन से गठिया का दर्द भी कम हो जाता है।

तनाव को दूर करने में: मछली के सेवन से उसमें होने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड से अवसाद की स्थिति में काफी फायदा मिलता है। ओमेगा-3 की कैप्सूल मिलती अवसाद से उबारने में काफी मददगार है।

त्वचा और बालों के लिए: मछली के सेवन से उसमें मिलने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड से त्वचा और बाल खूबसूरत बने रहते हैं। इससे त्वचा की नमी नहीं जाने पाती है और बाल भी चमकदार बने रहते हैं।

स्मरण शक्ति बढाने के लिए: मछली में मौजूद पोषक तत्व मस्तिष्क को तेज करने का काम करते हैं। मछली में मौजूद फैटी एसिड स्मरण शक्ति बढ़ाता है एवं दिमाग को तेज करता है। इसके साथ ही इसमें होने वाले प्रचुर प्रोटीन से शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है।

कैसर से बचाव: मछली का नियमित सेवन करते रहने से कैंसर होने का खतरा कम होता है। मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कैंसर से बचाव करता है। इसे खाने से विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलन एवं प्रोस्टेट कैंसर से बचाव होता है। आहार में मछली के इस्तेमाल से बहुत फायदा होता है।

हृदय की सुरक्षा के लिए: हाई ब्लड प्रेशर एवं हार्ट की बीमारी वालों के लिए मछली बहुत फायदेमंद है। मछली में पाया जाने वाला ओमेगा-3 फैटी एसिड हार्ट और उसकी मांस-पेशियों को मजबूत बनाता है। मछली में काफी कम फैट होने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने नहीं पाती है। ओमेगा-3 फैटी एसिड हृदय रोग को कम करता है। मछली का सेवन उच्च रक्त चाप को नियंत्रित करने में काफी मददगार है।

ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने के लिए: ट्राइग्लिसराइड एक विशेष प्रकार का वसा है, जो हमारे रक्तप्रवाह में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब रक्त में मौजूद ट्राइग्लिसराइड की मात्रा उसके मानक स्तरों से अधिक हो जाती है, तो हम मधुमेह और हृदय रोग सहित विभिन्न मेटाबॉलिक सिंड्रोम की चपेट में आ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में मछली के तेल में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड के स्तर को काफी कम कर सकता है ।

अच्छी नींद के लिए: मछली में पाए जाने वाला विटामिन डी अच्छी नींद के लिए फायदेमंद है।

ऑखों की रोषनी बढाने के लिए: मछली ऑखों के लिए कापी लाभकारी होती है इसमें मत्स्य तेल और ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ-साथ विटामिन ए होता है जिससे ऑखों की रोशनी बढती है।

हेल्दी स्पर्म (शुक्राणु) के लिए: पुरुषों द्वारा मछली के सेवन के साथ ही अच्छा आहार जैसे फल और दूसरी पौष्टिक चीजों का सेवन करने से स्पर्म (शुक्राणु) हेल्दी एवं सक्रिय होते हैं।

मछली में सैचुरेटेड (संतृप्त) वसा नहीं होता है। इस वजह से यह आपके स्वास्थ्य के लिए और विशेषकर हृदय संबंधी रोग के लिए लाभ दायक है।

मछली एक सुपरफूड: मछली हमेशा हर किसी की पसंदीदा नहीं होती, लेकिन यह निश्चित रूप से एक सुपरफूड है जिसे खाने लायक है। अगर मछली अब तक आपके आहार का नियमित हिस्सा नहीं रही है, तो इसे नए तरीकों से पकाने और अलग-अलग भोजन में शामिल करने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपको अपनी अगली पसंदीदा डिश मिल जाए।

गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए विचारणीय बातें: अधिक मछली खाने से सभी को लाभ हो सकता है, लेकिन कुछ समूहों को इस बात के बारे में अधिक सावधान रहना होगा कि वे किस प्रकार की मछली खाते हैं और कितनी मात्रा में। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पारे के नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं - और कुछ मछली प्रजातियों में दूसरों की तुलना में अधिक पारा होता है। गर्भवती महिलाओं को बिना पका हुआ समुद्री भोजन, जैसे सुशी या स्मोक्ड मछली खाने से भी बचना चाहिए।

सर्दियों में शुगर ग्लाइडर की देखभाल और उचित प्रबंधन

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. दीक्षा लाडे
» डॉ. आराधना मिश्रा
» डॉ. राहुल कुमार गांधी
» डॉ. दुर्गेश सिंह
» डॉ. सुरेश कुमार यादव
- पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू मध्य प्रदेश
- स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ,जबलपुर मप्र
- पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय रीवा, मप्र

शुगर ग्लाइडर छोटे, प्यारे, फुर्तीले और बेहद सामाजिक प्राणी हैं, जो मार्सुपियल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ठंडे मौसम में, इनकी देखभाल के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य है, क्योंकि इनके शारीरिक कार्य और व्यवहार पर मौसम का गहरा प्रभाव पड़ता है। ठंडे वातावरण में उनकी सेहत और खुशी सुनिश्चित करने के लिए उनकी जरूरतों को समझना और पूरा करना आवश्यक है।

शुगर ग्लाइडर ठंड के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। उनका सामान्य शरीर का तापमान लगभग 36-37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंडे मौसम में उनका शरीर ऊर्जा बचाने के लिए टॉरपोर की स्थिति में चला सकता है। **टॉरपोर का प्रभाव:** यह उनकी मेटाबॉलिक दर को कम करता है, जिससे ठंड से बचने में मदद मिलती है, लेकिन लंबे समय तक यह स्थिति उनके लिए हानिकारक हो सकती है। **तापमान बनाए रखना:** पिंजरे के आसपास का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। यह उनके थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम को स्थिर रखने में मदद करता है। **पोषण संबंधी आवश्यकताएं:** सर्दियों में ऊर्जा उत्पादन के लिए शुगर ग्लाइडर को उच्च कैलोरी और पोषण युक्त आहार की आवश्यकता होती है। **प्रोटीन की भूमिका:** शुगर ग्लाइडर की दैनिक प्रोटीन आवश्यकता उनके शरीर के वजन का 15-20प्रतिशत है। उबले अंडे या कीड़े इसका बेहतरीन ीत हैं। **कैल्शियम-फॉस्फोरस अनुपात:** सही अनुपात (2:1) बनाए रखना हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी है। ग्लूकोज का महत्व: शुगर ग्लाइडर अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा ग्लूकोज से पूरा करते हैं, जिसे वे फलों जैसे कि सेब, अंगूर और नाशपाती से प्राप्त करते हैं।

पर्यावरणीय समायोजन: शुगर ग्लाइडर के प्राकृतिक आवास में तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं होता, इसलिए कृत्रिम वातावरण में उन्हें सर्दी से बचाने के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। **थर्मल गियर का उपयोग:** फ्लीस कवर, हीटिंग पैड, और थर्मल पाउच उनके शरीर की गर्मी को बनाए रखते हैं। **नमी का ध्यान:** शुगर ग्लाइडर की त्वचा और श्वसन प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए कमरे में 40-60 प्रतिशत की आदर्श नमी बनाए रखें। अत्यधिक सूखी हवा उनके लिए हानिकारक हो सकती है। **सर्दियों में हाइबरनेशन और टॉरपोर का प्रभाव:** शुगर ग्लाइडर हाइबरनेशन में नहीं जाते, लेकिन ठंडे तापमान के कारण टॉरपोर की स्थिति में चले जाते हैं। **निगरानी आवश्यक है:** लंबे समय तक टॉरपोर में रहना उनके मेटाबॉलिज्म को कमजोर कर सकता है। अगर वे सुस्त या निष्क्रिय दिखें, तो तत्काल हीटर चालू करें और उनका तापमान सामान्य करें। **ऊर्जा की खपत:** सर्दियों में उनकी ऊर्जा खपत 20-30प्रतिशत तक बढ़ सकती है, इसलिए उनका आहार इसी के अनुसार समायोजित करें। **रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय:** सर्दियों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है। शुगर ग्लाइडर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। **विटामिन सप्लीमेंट्स:** उनके आहार में विटामिन सी और डी जोड़ें। ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं और ठंड के प्रभाव को कम करते हैं। **संक्रमण से बचाव:** पिंजरे और पाउच को नियमित रूप से साफ करें। बैक्टीरिया और फंगस का विकास सर्दियों में तेजी से होता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। **व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य:** शुगर ग्लाइडर अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं। ठंड में वे अधिक आरामदायक और सामाजिक संपर्क की आवश्यकता महसूस करते हैं। **साथी का महत्व:** यदि आपके पास एक से अधिक ग्लाइडर हैं, तो वे एक-दूसरे की गर्मी साझा करते हैं। **अकेलापन दूर करें:** यदि वे अकेले हैं, तो उनके साथ नियमित रूप से समय बिताएं। मानसिक सक्रियता बनाए रखने के लिए उनके साथ खेलें। सर्दियों में शुगर ग्लाइडर के व्यवहार और स्वास्थ्य पर नजर रखना जरूरी है। **ठंड के लक्षण:** यदि ग्लाइडर सुस्त, कम सक्रिय, या अधिक कांपते हुए दिखते हैं, तो यह ठंड का संकेत हो सकता है। **वेट चेक:** नियमित रूप से उनका वजन जांचें। सर्दियों में वजन कम होना स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। **वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग :** **थर्मामीटर और ह्यूमिडिटी मॉनिटर:** पिंजरे का तापमान और नमी मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करें। **पोषण मॉनिटरिंग ऐप्स:** कई ऐप उपलब्ध हैं जो शुगर ग्लाइडर के आहार का रिकॉर्ड रखने और आवश्यक पोषण की गणना करने में मदद करते हैं। सर्दियों में शुगर ग्लाइडर की देखभाल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना उनकी सेहत और खुशी के लिए अत्यधिक लाभकारी है।

माइक्रोप्लास्टिक और पीएफएएस के मिश्रण से पर्यावरण को होता है भारी नुकसानः अध्ययन

25 नवंबर से 175 देशों के प्रतिनिधि प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए, दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए पांचवें दौर की वार्ता के लिए एकत्र हुए, जो एक दिसंबर तक चलेगी। संधि वार्ता में प्लास्टिक में उपयोग होने वाले केमिकलों के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है।

एक नए अध्ययन से पता चलता है कि रोजमर्रा की वस्तुओं में उपयोग होने वाले केमिकलों का मिला जुला असर अलग-अलग केमिकलों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक हानिकारक है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने माइक्रोप्लास्टिक्स और पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ के पर्यावरणीय प्रभावों की जांच की और दिखाया कि दोनों जलीय जीवन के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक छोटे प्लास्टिक कण होते हैं जो प्लास्टिक की बोतलों, पैकेजिंग और कपड़ों के रेशों से आते हैं। पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ रसायनों का एक समूह है जिसका उपयोग रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे नॉन-स्टिक कुकवेयर, जल-प्रतिरोधी कपड़े, अग्निशमन फोम और कई औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। पीएफएएस और माइक्रोप्लास्टिक को फॉरएवर केमिकल के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे आसानी से नहीं टूटते हैं और पयाज़्वरण में जमा हो जाते हैं, जिससे वन्यजीवों और मनुष्यों दोनों के लिए इनसे खतरे पैदा हो सकते हैं। पीएफएएस और माइक्रोप्लास्टिक दोनों को जल प्रणालियों के माध्यम से लंबी दूरी तक, आर्कटिक तक ले जाया जा सकता है। वे अक्सर उपभोक्ता उत्पादों से एक साथ निकलते हैं। फिर भी उन दोनों के प्रभाव और जिस तरह से वे पर्यावरण में अन्य प्रदूषणकारी यौगिकों के साथ क्रिया करते हैं, उसे अभी भी ठीक से समझा नहीं गया है। इन प्रदूषकों के मिले जुले प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए, शोधकर्ताओं ने डैनफनिया का उपयोग किया, जिसे आमतौर पर पानी के पिस्सू के रूप में जाना जाता है। इन छोटे जीवों का उपयोग अक्सर प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है क्योंकि वे रसायनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे वे पर्यावरण में सुरक्षित रासायनिक सीमा निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छे हैं। एनवायर्नमेंटल पोलूशन नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में, टीम ने पानी के पिस्सू के दो समूहों की तुलना की: एक जो कभी रसायनों के संपर्क में नहीं आए थे और दूसरे जो अतीत में रासायनिक प्रदूषण से गुजर चुके हैं। यह अनोखा नजरिया डेफनिया की लंबे समय तक निष्क्रिय रहने की क्षमता के कारण संभव हुआ, जिससे शोधकर्ताओं को अलग-अलग प्रदूषण इतिहास वाली पुरानी आबादी को फिर से जीवित करने में मदद मिली।

बुरहानपुर जिले के धूलकोट में छापेमारी के बाद निजी फर्म का गोदाम सील

सावधान! आदिवासी अंचलों में बिक रही नकली खाद

बुरहानपुर। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के ग्रामीण आदिवासी अंचल धूलकोट में खाद दुकानों पर बिक रहे नकली खाद की शंका में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल, यहां की कुछ दुकानों से खाद खरीदने के बाद किसानों को उस खाद में रेत और मिट्टी के मिलावट का शक था, जिसको लेकर पीड़ित किसानों ने आदिवासी संगठन जायस की मदद ली। इसके बाद जयस संगठन के सदस्यों ने तहसीलदार सहित कृषि अधिकारी को इसकी जानकारी दी और गांव की एक निजी फार्म पर प्रशासन के संयुक्त अमले ने छापामार कार्रवाई की। यहां धूलकोट स्थित शैफाली एग्रो के खाद गोदाम में मारे गए छापे के दौरान गोदाम से डीएपी और पोटाश सहित जिंक पाउडर के नमूने लिए गए एवं नमूनों की जांच रिपोर्ट आने तक गोदाम को सील किया गया है। कार्रवाई के बाद से धूलकोट क्षेत्र के खाद बीज बेचने वाले विक्रेताओ में हडकंप मचा हुआ है और कुछ विक्रेता तो फिलहाल अपनी दुकाने खोलने से भी कतरा रहे हैं। वहीं, जयस कार्यकर्ताओं ने नकली खाद बीज का व्यापार संचालित होने वाली खाद बीज की दुकानों का निरीक्षण कर उन पर उचित कार्रवाई की मांग की है।

डी ए पी
DAP
18-46-0
उर्वरक FERTILISER

पूरे धुलकोट में इस्तेमाल हो रही खाद

जयस के जिला अध्यक्ष टीएस जाधव ने बताया कि डीएपी वगैरह जो मार्केट में आ रही है, उसकी हमारे पास किसानों की शिकायत आई थी। इस पर अभी जांच पड़ताल हुई है। इसमें काफी मात्रा में अभी डुप्लीकेट डीएपी निकली है और इस पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पूरा धूलकोट बेल्ट आज इस खाद का इस्तेमाल कर रहा है। इस नकली माल से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी उचित जांच होना चाहिए। हमने पहले भी मांग की थी कि यहां की सारी ढुकानों का निरीक्षण होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अगर अब कार्रवाई नहीं होती है तो जयस संगठन इसके लिए धरना और आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।

जांच के बाद गोदाम को किया सील

जांच करने पहुंचे वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्रीराम पाटील ने बताया कि धूलकोट में तहसीलदार और कृषि विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा शेफाली एग्रो का निरीक्षण किया गया था। जहां की एक किसान के द्वारा शिकायत मिली थी कि खाद में रेत या किसी अन्य चीज की मिलावट की गई है। इसके निरीक्षण में पाया कि रामा कंपनी का डीएपी और श्री विनायक कंपनी का पोटाश और आइडियल क्राफ्ट केयर का जिंक जिसके हमने नमूने लिए हैं और यहां पर श्री विनायक फर्टिलाइजर के और रामा कंपनी के कोई भी दस्तावेज डीलर नहीं दिखा पाया है, जिसका हमने तहसीलदार साहब के समक्ष में पंचनामा बनाया और उसके सारे माल को जब्त कर उसी डीलर के

नागपुर में आयोजित एग्रो विजन राष्ट्रीय कृषि मेले में कार्यशाला का आयोजन

एक जिला-एक उत्पाद की तर्ज पर लगाई जाएगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट : उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद की तर्ज पर उद्यानकी फसलों की प्रोसेसिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत कार्य-योजना तैयार की जायेगी। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने रविवार को नागपुर में आयोजित एग्रो विजन राष्ट्रीय कृषि मेले में आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना जिला और संभाग लेवल पर हो जाने से उत्पादक किसानों को उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। मंत्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में 20 वर्षों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। खेती-किसानी को सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। किसान भाई परंपरागत खेती के स्थान पर कैश क्रॉप के प्रति आकर्षित हुए हैं, उन्होंने कहा कि मप्र सरकार का प्रयास है कि उद्यानकी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को फसल का सही दाम मिल सके। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट और माकेर्ज़टिंग का काम प्राथमिकता के साथ किया जाएगा।

मप्रमें नागपुर की तर्ज पर होगी संतरे की खेती

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री कुशवाहा ने नागपुर में पैदा किये जा रहे हैं ऑर्गेनिक संतरे की फसल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मप्र में भी संतरे का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। संतरे की फ़सल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के किसानों को नागपुर स्टडी टूर पर भेजा जाएगा, जिससे किसान भाई ऑर्गेनिक संतरे की उत्पादन प्रक्रिया को देख और समझ सकेंगे।

मप्र में खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए बेहतर माहौल

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह शनिवार को नागपुर में एग्रोविजन राष्ट्रीय कृषि मेले में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। मध्यप्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए बेहतर माहौल है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयों को केंद्र के साथ राज्य सरकार भी विशेष अनुदान मुहैया कराती है। मंत्री कुशवाह ने कृषि मेले में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और मेले के आयोजन को कृषकों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि एग्रोविजन मेले में स्टार्टअप्स एवं नवीन तकनीकियों, उन्नत खाद्य एवं बीज, कृषि उपकरणों के प्रदर्शन के साथ किसान भाईयों और उद्यमियों को नवीन इकाइयों की स्थापना के लिये शासन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इससे वे योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। मंत्री कुशवाह ने कहा कि इस तरह के मेले देश के अन्य राज्यों में भी आयोजित किया जाना चाहिए। मंत्री कुशवाह ने राष्ट्रीय कृषि मेले में शामिल हुई विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर, उन्हें मध्यप्रदेश आने का आमंत्रण दिया। श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रचुर संभावनाएं हैं। वर्ष 2023-24 में 4.30 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की बोनी की गई, इसमें 96 लाख 11 हजार मीट्रिक टन से अधिक उद्यानिकी फसलों का उत्पादन हुआ है, जो रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश में संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन और मसाला फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राज्य सरकार खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित कर रही है, मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है इस कारण भारत सरकार द्वारा प्रदेश में इस योजना की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई है। अब यह योजना प्रदेश में मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। योजना में खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में काम करने वाली निजी इकाइयों को 35प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाता है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण अनुपम राजन, आयुक्त हथकरघा एवं प्रबंध संचालक संत रविदास हस्तशिल्प विकास निगम मदन कुमार सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

कुकीज मेकिंग यूनिट बेचने में अनियमितता पर कलेक्टर का एक्शन

जबलपुर में 2.5 लाख की मशीन स्व सहायता समूह को दस लाख में दी

जबलपुर। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व-सहायता समूह के लिए कोदो-कुटकी से कुकीज बनाने की मशीनों (कुकीज मेकिंग यूनिट) की खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। इस कारण कलेक्टर दीपक सक्सेना ने वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी कर समूह को आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक अखिल शुक्ला को उनकी संविदा सेवा समाप्त करने का नोटिस जारी किया है। जिला प्रबंधक लघु उद्यमिता विकास एवं प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक ग्रामीण आजीविका मिशन अखिल शुक्ला को सप्लायर के साथ मिलीभगत से जनपद पंचायत कुंडम के ग्राम तिलसानी के सरस्वती आजीविका मिशन को वाटरशेड आजीविका मद एवं बैंक ऋण के माध्यम से घटिया मशीनें अधिक कीमत पर उपलब्ध कराने दोषी पाया गया है।

जनसुनवाई में भी लगाई गुहार...

धोखाधड़ी की यह शिकायत खुद सरस्वती आजीविका समूह की सदस्यों ने जनसुनवाई में कलेक्टर सक्सेना से की थी। कलेक्टर ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही जिला पंचायत के सीईओ को जांच करने के निर्देश दिए थे। जिला पंचायत सीईओ द्वारा की गई जांच में पाया गया कि प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक अखिल शुक्ला द्वारा सप्लायर मेसर्स एसएस बेनीप्रसाद धरमचंद जैन के ऋत्विक जैन के साथ मिलीभगत कर दो लाख 53 हजार रुपए की कुकीज मेकिंग यूनिट 10 लाख 06 हजार रुपये में सरस्वती आजीविका मिशन को थमा दी। जांच में इन मशीनों की गुणवत्ता को भी स्तरहीन पाया गया।

जांच में स्थल पर चाइना मेड मशीन पाई गई

सीईओ जिला पंचायत ने जांच प्रतिवेदन में बताया कि कुकीज मेकिंग यूनिट की मशीनें सही ढंग से इंस्टाल भी नहीं की गई थीं और न ही इनका प्रशिक्षण समूह की सदस्यों को दिया गया। इसके साथ ही कुकीज मेकिंग यूनिट में शामिल स्पाइरल मिक्सर का दो लाख 12 हजार 400 रुपए का भुगतान सप्लायर को करा दिया गया, जबकि जांच में स्थल पर चाइना मेड मशीन पाई गई और उस पर 22 हजार रुपये की कीमत भी अंकित थी। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने महिला स्व-सहायता समूह को आर्थिक क्षति पहुंचाने और प्रशासन की छवि धूमिल करने के इस मामले में प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर उन्हें 29 नवंबर की सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर समक्ष में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है।

होलोग्राम आधारित विकास के 4 स्तंभ आगंतुकों को कर रहे आकर्षित

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश मंडप बने आकर्षण का केंद्र

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश मंडप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंडप में मेले की थीम 'विकसित भारत-2047' के अनुरूप प्राचीन सांस्कृतिक एवं कलात्मक धरोहर के साथ तेजी से विकसित होते मध्यप्रदेश के स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। मंडप में प्रदेश के विकास और समृद्धि के डिजिटल निरूपण के साथ ही प्रदेश के पर्यटन गंतव्य, जनजातीय एवं लोक-कला तथा स्थापत्य कला को मनमोहक तरीके से प्रदर्शित किया गया है।

मिल रही विकास की तकनीकी झलक- मंडप में प्रवेश करते ही होलोग्राम आधारित विकास के 4 स्तंभ दर्शाए गए हैं। अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए कांच के स्तंभों के भीतर होलोग्राम के माध्यम से युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब कल्याण और किसान कल्याण मिशन प्रदर्शित किए गए हैं। ये 4 स्तंभ आगंतुकों, विशेषकर युवाओं और बच्चों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। डिजिटल इन्फो पैनल्स के माध्यम से प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रहीं रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और उद्योग वर्ष की परिकल्पनाओं को प्रमुखता से दर्शाया गया है।

विरासत और विकास का संगम

मंडप के प्रवेश द्वार पर सांची स्तूप, ग्वालियर किला, खजुराहो की मूर्तिकला, चंदेरी द्वार और अमरकंटक कुंड दर्शाए गए हैं। मंडप की बाहरी हिस्से में प्रदेश की 4 प्रमुख जनजातियां-गोंड, भील, सहरिया और बैगा के रहन-सहन और वेशभूषा की विस्तृत जानकारी दी गई है। मंडप के दूसरी ओर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क, गांधी सागर डैम और रीवा अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र जैसी परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। मंडप के भीतरी हिस्से में ऊपर की ओर प्रदेश के प्रमुख गंतव्य स्थलों के पैनल्स लगाए गए हैं।

सिंचाई की फव्वारा तकनीक से रोका जा सकता है जल का दुरुपयोग

वैज्ञानिक तरीके से सिचांई और खाद प्रबंधन से फसल उत्पादन में होगा इजाफाः डॉ. रनाडे

बड़वानी। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी द्वारा कृषि आदान विक्रेताओं के एकवर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम (देसी) अन्तर्गत प्रषिक्षण कार्यक्रम प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसके बड़ोदिया के मार्गदर्शन में केन्द्र के सभागार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वक्ता के रूप में अधिष्ठाता-बीएम कृषि महाविद्यालय खंडवा डॉ. डीएच रानाडे द्वारा भागीदारी की गई। सर्वप्रथम अधिष्ठाता डॉ.रानाडे ने कहा कि छोटी-छोटी सी सावधानियां और प्रबंधन कार्य कर फसल के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है-जैसे अपने खेत की मृदा अनुसार फसल का चयन, उपयुक्त प्रजाति का चुनाव, सिचांई और उर्वरक का समुचित प्रबंधन कर 30-40 प्रतिषत तक उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है। अगर फसल में ड्रिप सिचांई पद्धति से सिंचाई की जाए व उचित उर्वरक प्रबंधन किया जाए तो फसल में अच्छा उत्पादन देखा गया है। इसके साथ ही साथ इस अवसर पर कहा कि हमें जल प्रबंधन की शुरुआत कृषि क्षेत्र से करनी चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में कृषि कार्यों में ही जल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई में जल का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है। जनमानस में धारणा है अधिक पानी, अधिक उपज, जो कि गलत है, क्योंकि फसलों के उत्पादन में सिंचाई का योगदान 15-16 प्रतिशत होता है।

धरती के गर्भ से पानी की आखिरी बूंद भी खींचने की कवायद की जा रही

फसल के लिए भरपूर पानी का मतलब मात्र मिट्टी में पर्याप्त नमी ही होती है परंतु वर्तमान कृषि पद्धति में सिंचाई का अंधा-धुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। धरती के गर्भ से पानी की आखिरी बूंद भी खींचने की कवायद की जा रही है। देश में हरित क्रांति के बाद से कृषि के जरिये जल संकट का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बूँद-बूँद सिंचाई बौछार (फव्वारा तकनीकी) तथा खेतों के समतलीकरण से सिंचाई में जल का दुरुपयोग रोका जा सकता है। फसलों के जीवन रक्षक या पूरक सिंचाई देकर उपज को दुगुना किया जा सकता है। जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए पौधों को संतुलित पोषक तत्वों को प्रबंध करने की आवश्यकता है, जल की सतत् आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि भूमिगत जल का पुनर्भरण किया जाए, खेतों के किनारे फलदार वृक्ष लगाने चाहिए, छोटे-बड़े सभी कृषि क्षेत्रों पर क्षेत्रफल के हिसाब से तालाब बनाने जरूरी है। रासायनिक खेती की बजाय जैविक खेती पद्धति अपना कर कृषि में जल का अपव्यय रोका जा सकता है। ऊंचे स्थानों, बांधों इत्यादि के पास गहरे गड्ढे खोदे जाने चाहिए, जिससे उनमें वर्षा जल एकत्रित हो जाए और बहकर जाने वाली मिट्टी को अन्यत्र जाने से रोका जा सके, कृषि भूमि में मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए हरित खाद तथा उचित फसल चक्र अपनाया जाना चाहिए। काबर्जनिक अवशिष्टों को प्रयोग कर इस नमी को बचाया जा सकता है। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए शहरी मकानों में आवश्यक रूप से वाटर टैंक लगाए जाने चाहिए। इस जल का उपयोग अन्य घरेलू जरुरतों में किया जाना चाहिए। जल का संरक्षण करना वतज्र्मान समय की आवश्यकता है। इस अवसर पर डॉ.रानाडे द्वारा केन्द्र की प्रदर्शन इकाइयों बकरी पालन, मुर्गीपालन, केंचुआ खाद इकाई, एजोला इकाई, डेयरी आदि का अवलोकन कर सराहना की।

प्रो. डीपी सिंह को अकादमिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

एटा जनपद के नगला खुशाल सिंह,जलेसर के मूल निवासी और आगरा विश्व विद्यालय के आरबीएस कॉलेज के पूर्व छात्र, विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व चेयरमैन प्रो.धीरेंद्र पाल सिंह को अकादमिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड-2024 से नवाजा गया है।

यह सम्मान डॉ. प्रीतम सिंह फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद में आयोजित चौथे प्रिज्म सम्मेलन के समापन समारोह में प्रो. सिंह को चार दशक तक निर्वाध अकादमिक नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार देश के प्रमुख शिक्षाविदों, लोक सेवकों और नीति निर्माताओं की जूरी की अनुशंसा पर प्रदान किया जाता है। चार दशकों तक अकादमिक नेतृत्व का अनुभव रखने वाले विख्यात शिक्षाविद् प्रो. डीपी सिंह वर्तमान में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुम्बई के कुलाधिपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार हैं। इससे पूर्व विवि अनुदान आयोग के चेयरमैन, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक, बनारस हिंदू विवि, वाराणसी, डॉ. हरि सिंह गौर विवि, सागर, देवी अहिल्या विवि, इंदौर के कुलपति रह चुके हैं।

यूपी रत्न भी मिल चुकाः केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यान्वयन समिति आदि के पदेन सदस्य के रूप में योगदान कर चुके हैं। इस प्रकार, प्रो. सिंह के पास भारतीय उच्च शिक्षा के कई अकादमिक संस्थाओं का नेतृत्व करने का अनुभव है। इससे पूर्व सिंह को पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, दशक के पर्यावरणविद् (पूर्वांचल) पुरस्कार, भारत ज्योति पुरस्कार, यूपी रत्न पुरस्कार, आगरा विवि गौरव श्री पुरस्कार, राजा बलवंत सिंह शिक्षा सम्मान, राष्ट्र निर्माता पुरस्कार समेत दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

वैज्ञानिक सलाहकार समिति की हुई बैठक

कृषि विज्ञान केंद्र श्री अन्न फसलों के प्रदर्शन गांवों में करें

मंदसौर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, मंदसौर की रबी 2024-25 की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक गत दिवस हाईब्रीड मोड़ में डॉ. आईएस तोमर, अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जिसमें डॉ. जीएस चुंडावत, प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र, मंदसौर ने प्रगति प्रतिवेदन खरीफ 2024 एवं रबी 2024-25 की प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। साथ ही फसल परीक्षणों एवं प्रदर्शनों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। इस बैठक में अधिष्ठाता ने अपने अध्यक्षीय उदबोद्घन में कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र श्री अन्न फसलों के प्रदर्शन कृषक प्रक्षेत्रों पर भी आयोजित किए जाएं, जिससे कि उनकी तुलना परम्परागत फसलों से की जा सके। साथ ही उनके विपणन की भी जानकारी किसानों को दी जाकर उनसे होने वाले लाभों से अवगत कराया जा सके। कार्यक्रम में निदेशक, अटारी जोन-9, आईसीएआर, जबलपुर के प्रतिनिधि एवं प्रधान वैज्ञानिक के रूप में डॉ. शालिनी चक्रवर्ती ने कहा कि केन्द्र फसलों के उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ फसलों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर भी कार्यक्रमों को अपनी कार्य योजना में शामिल करें।

वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने भी दिए अपने-अपने सुझाव

इस कार्यक्रम में निदेशक विस्तार सेवाएं, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि.,ग्वालियर के प्रतिनिधि एवं वैज्ञानिक के रूप में डॉ. आरसी आसवानी ने सुझाव दिया कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर परीक्षण व प्रदर्शन आयोजित करें। कार्यक्रम में डॉ. सीपी पचैरी, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, केवीके,नीमच, डॉ. सर्वेश त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, केवीके,रतलाम, अनिता धाकड़, उप संचालक कृषि विभाग, केएस सौलकी, उपसंचालक उद्यानिकी विभाग, डॉ. मनीष इंगोले, उपसंचालक पशुपालन विभाग, संजय भारद्वाज, महिला एवं बाल विकास विभाग, सुनील कुमार पाटील, कृषि अभियांत्रिकी विभाग, डॉ. केसी मालवीय, आयुष विभाग, चेतन पाटीदार, एसएडीओ कृषि विभाग, रविकांत, बीज प्रमाणीकरण संस्था, देवेन्द्र वर्मा, दूरदर्शन भोपाल, आदित्य पाटीदार, इफ्को, टीकमचंद्र, सॉलिडर्ड संस्था, आरजी गुप्ता, बायफ फाउंडेशन, सुयश गर्ग, प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह, समरथ धाकड़ एवं जितेंद्र सिंह एफपीओ प्रतिनिधि तथा जिले के उत्कृष्ट कृषक ईश्वरलाल पाटीदार, मधुसुदन धाकड़ ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर डॉ. एसपी त्रिपाठी, संतोष पटेल एवं राकेश अस्के भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राजेश गुप्ता एवं आभार डॉ. निशिथ गुप्ता ने व्यक्त किया।

तेंदूखेड़ा ब्लॉक के 95 फीसदी घरों में पहुंच रहा नर्मदा जल

योजना के संचालन से ब्लॉक में पानी के टैंकरों की सप्लाई बंद, वार्ड में प्रतिदिन 1.5 एमएलडी की जा रही पानी सप्लाई

तेंदूखेड़ा। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक में पानी की किल्लत दूर हो गई है। अब यहां नर्मदा जल पहुंच गया है। जबलपुर के लमेटा घाट से नर्मदा पेयजल योजना के तहत पानी पहुंचाया गया है। नर्मदा परियोजना के कारण अब लगभग हर घर नर्मदा जल पहुंच रहा है। गौरतलब है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से संचालित नर्मदा पेयजल योजना को भेड़ाघाट के नाम से जाना जाता है। नर्मदा पेयजल योजना का भेड़ाघाट, पाटन, कंटगी, मझौली, पनागर, सिहोरा और दमोह जिले का तेंदूखेड़ा ब्लॉक के हर घर को लाभ मिलेगा। सातों निकायों में अगले कई वर्षों की जरूरत के अनुसार सप्लाई लाइन तैयार की गई है। क्षेत्रवार योजना का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दरअसल, नगर परिषद तेंदूखेड़ा में इस समय नर्मदा जल योजना के तहत लगभग 95 फीसदी घरों में पानी पहुंचने लगा है। इससे वार्डवासियों को पानी की किल्लत से छुटकारा मिल गया है। अब पानी के लिए कुआं, बोर या अन्य जगह रहवासियों को कतार में नहीं लगना पड़ता है।

टैंकरों की सप्लाई बंद

लमेटा घाट पर बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (31 एमएलडी) से पानी को फिल्टर करके जबलपुर के छह टाउन और दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। योजना के संचालन से लोगों को इतना लाभ हुआ कि नगर में पानी के टैंकरों की सप्लाई बंद कर दी गई है।

दो बड़ी टंकियां भी बनाई गईं

उल्लेखनीय है कि मप्र सरकार का लक्ष्य है कि हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा। यहां उक्त योजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। यही नहीं, नगर में पानी की दो बड़ी-बड़ी टंकियां भी बनाई गई हैं। इन दोनों टंकियों से प्रतिदिन 1.5 एमएलडी के करीब पानी सप्लाई भी की जा रही है।

तेंदूखेड़ा नगर परिषद के सभी वार्डों में निरंतर पानी की सप्लाई की जा रही है। नगर में जो थोड़े बहुत कार्य बचे हैं, उन्हें तेजी से पूरा कराया जा रहा है। जल्द ही शेष कार्य करा लिया जाएगा। काम में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट से जुड़े हर कर्मचारी इमानदार के साथ दिन-रात काम में लगे हुए हैं।

-अभिषेक गौतम, प्रोजेक्ट इंचार्ज

-गत वर्ष की तुलना में इस बार बढाया गेहूं की बोवनी का रकवा, सरसों और चने का घटाया

83 हजार हेक्टेयर में होगी गेहूं की बोवनी, 70 हजार हेक्टे. में लहलहाएगी सरसों की फसल

अच्छी बारिश के चलते गेहूं की फसल अच्छी होनें की उम्मीद,बोवनी में जुटे किसान

जिले में इस साल हुई अच्छी बारिश के चलते खेती किसानी पर भी हुआ है। अच्छे उत्पादन की उम्मीद में इस बार गेहूं की बोवनी का रकवा बढ़ाया गया है। पिछली बार 74 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की गई थी। लेकिन इस बार गेहूं की बोवनी 83 हजार हेक्टेयर में होगी। जबकि 13 हजार 500 हेक्टेयर में चना और 70 हजार हेक्टेयर में सरसों की फसल लहलहाएगी। किसानों ने खेतों को तैयार करते हुए बोवनी की काम शुरू कर दिया गया है। आगामी दिनों में फसल की बोवनी के काम में तेजी आएगी। सिंचाई के लिए चंबल दाहिनी मुख्य नहर में पानी का प्रवाह भी शुरू हो गया है।

श्योपुर। जागत गांव हमार

कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग ने वर्ष 2024-2025 के लिए रबी फसल की बोवनी का लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। इस बार 1 लाख 68 हजार 760 हेक्टेयर में रबी फसलों की बोवनी की जाएगी। कृषि विभाग ने पिछली साल की बोवनी को देखते हुए इस बार गेहूं की बोवनी के लिए 9 हजार हेक्टेयर से ज्यादा रकवा बढ़ाया है। अच्छी बारिश के चलते गेहूं का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद में गेहूं की बोवनी के लिए 83 हजार हेक्टेयर रकवा तय किया है। जबकि पिछली बार 74 हजार हेक्टेयर रकवा गेहूं की बोवनी के लिए तय किया था और किसानों ने इससे ज्यादा रकवे में गेहूं की बोवनी की थी। सरसों और चने की बोवनी के लिए रकवा घटाया है। क्योंकि पिछले साल सरसो और चने की बोवनी तय लक्ष्य के मुताबिक नहीं हो पाई थी। बता दे कि पिछले साल यानि वर्ष 2023-2024 में सरसो की बोवनी के लिए 73 हजार और चने के लिए 17 हजार 500 हेक्टेयर में बोवनी का टारगेट लिया था, मगर टारगेट के मुकाबले सरसो की बोवनी 72 हजार हेक्टेयर के करीब और चने की बोवनी 14 हजार हेक्टेयर के करीब हुई थी। इसलिए इस बार सरसों की बोवनी के लिए रकवा कम किया है। बताया गया है कि इस बार 70 हजार हेक्टेयर में सरसों और 13 हजार 500 हेक्टेयर में चने की बोवनी का किया जाना तय हुआ है।

बीते दो साल में रबी फसल की बोवनी का लक्ष्य और पूर्ति

फसल	वर्ष 2023-24	पूर्ति	वर्ष 2024-2025	पूर्ति
गेहूं	74000 हेक्टेयर	74040 हेक्टेयर	83000 हेक्टेयर	4500 हेक्टेयर
जौ	900 हेक्टेयर	880 हेक्टेयर	900हेक्टेयर	250हेक्टेयर
चना	17500हेक्टेयर	14300 हेक्टेयर	13500 हेक्टेयर	5500हेक्टेयर
मटर	4800 हेक्टेयर	5000 हेक्टेयर	600 हेक्टेयर	550 हेक्टेयर
सरसों	73000 हेक्टेयर	72500 हेक्टेयर	70000 हेक्टेयर	67500 हेक्टेयर
अलसी	250 हेक्टेयर	240 हेक्टेयर	300 हेक्टेयर	170 हेक्टेयर
गन्ना	100 हेक्टेयर	110 हेक्टेयर	150 हेक्टेयर	30 हेक्टेयर
अन्य	2100 हेक्टेयर	3900 हेक्टेयर	00	300 हेक्टेयर

67 हजार में सरसों और 4500 हेक्टेयर बोया जा चुका गेहूं

जिले के किसान रबी फसल की बोवनी के काम में जुट गए है और किसानों के द्वारा गेहूं और सरसों सहित अन्य फसलों की बोवनी करना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग के मुताबिक अभी तक जिले के किसानों ने 4500 हेक्टेयर में गेहूं की फसल की बोवनी कर दी है। जबकि 67 हजार 500 हेक्टेयर में सरसों की बोवनी का काम भी पूरा हो चुका है। बताया गया है कि आगामी दिनो में बोवनी का काम तेज होगा और तय लक्ष्य के मुताबिक बोवनी का काम लगभग पूरा हो जाएगा।

अच्छी बारिश से गेंहू का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद

जिले में इस बार मानसूनी बारिश काफी अच्छी हुई है। जिले में औसत बारिश का आंकडा 822 मिमी है। लेकिन इस बार इससे ज्यादा बारिश जिले में हुई है। जिसके चलते भूजल स्तर की स्थिति अच्छी होने के साथही नदी तालाब और डैमों में भी पर्याप्त पानी एकत्रित हो गया है। उधर गांधीसागर बांध में भी पानी की मात्रा पर्याप्त होने की वजह से चंबल दाहिनी मुख्य नहर में भी पानी का प्रवाह मार्च के पूरे महिने तक चलने की उम्मीद है। ऐसे में किसानों को गेहूं की फसल का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद दिख रही है। इस उम्मीद के बूते किसान पूरी तैयारी के साथ बोवनी के काम में जुट गए है और किसानों के द्वारा खाद का इंतजाम भी किया जा रहा है।

सीएम डॉ. मोहन बोले-किसान हितैषी सरकार

मध्यप्रदेश में निरंतर बढ़ रहा सिंचाई का रकबा

भोपाल। जागत गांव हमार

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है, जो सबसे ज्यादा फिक्र अपने अन्नदाता की करती है। सरकार निरंतर हर खेत तक पानी पहुंचाने के कार्य कर रही है। जल संसाधन विभाग की विभिन्न वृहद, मध्यम एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से मध्यप्रदेश में निरंतर सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो जाने से अब किसान 2 फसलों के स्थान पर 3 फसल लेने लगे हैं। इससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और किसान समृद्ध भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 में जहां प्रदेश का सिंचाई रकबा 3 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़कर 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश की निर्मित और निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश में वर्ष 2025-26 तक सिंचाई का रकबा 65 लाख हेक्टेयर होने की संभावना है।

एक करोड़ हेक्टेयर का लक्ष्य

सीएम ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रदेश में तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। सरकार ने विभाग के लिए बजट में भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। वर्ष 2024-25 के बजट में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

केन नदी पर बनाएंगे दौधन बांध

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं में केन-बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी नदी जोड़ों राष्ट्रीय परियोजना है। इसमें केन नदी पर दौधन बांध, आनुषंगिक कार्य एवं लिंक नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के अंतर्गत बेतवा कछार में बीना काम्पलेक्स, कोटा बैराज तथा लोअरओर परियोजनाओं का निर्माण किया जाना शामिल है।

एमपी-यूपी को मिलेगा पानी

परियोजना से मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं दमोह जिलों में माइक्रो इरिगेशन से केन कछार में 4.5 लाख हेक्टेयर, बेतवा कछार के विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी एवं दतिया जिलों में 2.06 लाख हेक्टेयर तथा उत्तरप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, महोबा और झांसी जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के साथ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना से उत्पन्न होने वाली 103 मेगावाट जल विद्युत तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पर पूरा अधिकार मप्र का होगा।

द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर

मध्यप्रदेश में द्वितीय चरण की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रि-परिषद द्वारा 44 करोड़ 605 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना को 8 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त

परियोजना के द्वितीय चरण की डीपीआर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2014 में तैयार की गई। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश द्वारा बेतवा कछार में अंतिम रूप से प्रस्तावित 3 परियोजनाएं-बीना परिसर से 96 हजार हेक्टेयर, कोटा बैराज से 20 हजार हेक्टेयर तथा लोअर ओर परियोजना से 90 हजार हेक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है। साथ ही परियोजनाओं से 66.7 मिलियन घन मीटर पेयजल एवं मांग आधार पर उद्योगों के लिए जल का प्रावधान रखा गया है। परियोजना की सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं।

त्रिपक्षीय समझौता हुआ

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके लिए मप्र, राजस्थान और केंद्र के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों को लाभ मिलेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती-कालीसिंध परियोजना और नर्मदा घाटी की अन्य प्रस्तावित अहम परियोजनाओं से प्रदेश में 19 लाख 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। प्रदेश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वृहद् एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजना निर्माणाधीन है।

सिंगरौली होगा पानी-पानी

प्रदेश में 1320 करोड़ रुपए की लागत वाली चितरंगी दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है। इस परियोजना से सिंगरौली जिले में 32 हजार 125 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा। इसी प्रकार 4197 करोड़ 58 लाख की लागत से जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृत किया गया है। नीमच जिले में इस परियोजना से 18 हजार 600 हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)
ईमेल-द्यह्वड्डद्गह्व.ह्वड्डद्बञ्चद्दद्बड्डद्य.ष्शद्व, मोबा- 7985680406

2. प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,
आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दड्डढ्ढह्म्द्बद्ग4ड्डद्य.द्यड्डद्य ञ्चद्यद्धद्दड्डह्लह्य.द्गस्रह्व.द्बठ्ठ, मोबा- 7052657380

3. डा. वीरेन्द्र कुमार, प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com
मोबा- 8210231304

4. डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncgupt-abau@gmail.com, मोबा- 8789708210

5. डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान)
कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश)
सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र)
ईमेल- dpatil889@gmail.com,मोबा- 8827176184

6. डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र
ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901

7. डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र
ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144

8. डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार।
ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793

9. डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक, मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड।
ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836

10. डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार।
ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670

11. रोमा वर्मा, सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।
ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

देश के दुग्ध उत्पादन का 20 फीसदी मध्यप्रदेश से करने का लक्ष्य

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9 प्रतिशत उत्पादन मध्यप्रदेश में होता है। इसे 20 प्रतिशत तक ले जाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। सीएम मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में संगठित क्षेत्र में दुग्ध संकलन बढ़ाने और सहकारी दुग्ध संघ और महासंघ के सुदृढ़ीकरण के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन के प्रयासों में वृद्धि की जाएगी। प्रदेश के जिन ग्रामों में सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, वहां दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही शेष ग्रामों के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राजगढ़ जैसे जिलों में किसान उत्पादक संगठन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से उत्साहपूर्ण पहल कर चुके हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारिता से जुड़े नियमों और अधिनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन की कार्यवाही भी की जाएगी।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः** अरविंद मिश्रा, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)